tension of rliefs' and concessions generally and those specially meant for PSUs be adopted as a matter of right. These alongwith other elements of the rehabilitation package, have to be followed/accepted in consensus among all the bank/financing institutions and other agencies participating in the rehabilitation package. In the case of sick industrial companies including PSUs such packaging would need to be sanctioned by the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR).

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का आर्थिक स्तर

4389. **श्री जगन्नाथ सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार देश की कुल आबादी में से कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे की जिन्दगी जीने के लिए मजबूर हैं ; और

(ख) ऐसे व्यक्तियों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कार्यक्रम तैयार किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : गरीबी के प्रभाव का राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान (एन एस एस ओ) द्वारा पूरा किए गए घरेलू खपत व्यय के पंचवर्षीय सर्वेक्षण के आधार पर अनुमान लगाया गया है । गरीबी उन्मूलन संबंधी नवीनतम सरकारी अनुमान वर्ष 1987-88 के लिए उपलब्ध हैं। अनुमान के अनुसार, वर्ष 1987-88 में जनसंख्या का 29.9 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे था । वर्ष 1993-94 के दौरान हुए पंचवर्षीय सर्वेक्षण का परिणाम अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है ।

(ख) गरीबों के जीवन स्तर और आर्थिक स्तर में सुधार करने के लिए बड़ी संख्या में विशेष रोजगार और गरीबी उन्मूलनज कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है । इनमें समेकित ग्रामीण विकास (आई आर डी पी), जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई), नेहरू रोजगार योजना (एन आर वाई), रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस) और प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी एम आर वाई) शामिल हैं । इन कार्यक्रमों के लिए आवंटन पिछले तीन केन्द्रीय बजटों के दौरान पूरी तरह से बढ़ा दिया गया है ।

Loans released to Agriculture Sentor

4390. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what was the percentage of the agriculture sector to the national income during 1993-94 and 1994-95; and

(b) what is the percentage of the loan amount released to the agriculture sector from the national income during 1993-94 and 1994-95?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) and (b) The information is being collected and, to the extent available, will be laid on the Table of the House.

Loan extended by A.D.B.

4391. SHRI JAGESH DESAI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Asian Development Bank has recently extended a loan of $ 245 million (Rs. 772 crores) for improvement of five national highways in India as per the agreemet signed by Government with A.D.B.; and

(b) if so, when it is likely to come into force?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) An agreement for National Highway Project (Loan No. 1274—IND) for US $ 245 million was signed on 22.03.1995 with A.D.B.